एआरएफ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

मध्यस्थता अपील संख्या 23/2020

एम/एस मनीष पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशक जगदीश झावर के माध्यम से, आयु लगभग 60 वर्ष, जिसका कार्यालय मर्लिन जय श्री विहार, पांडरी तराई, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ---अपीलार्थी

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उप सचिव के माध्यम से, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. छत्तीसगढ़ राज्य, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता के माध्यम से, नीर भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़
3. छत्तीसगढ़ राज्य, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परियोजना प्रभाग के कार्यपालक अभियंता के माध्यम से, रायपुर, छत्तीसगढ़ ---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के लिए :- श्री विवेक चोपड़ा, अधिवक्ता
उत्तरवादी /राज्य के लिए :- श्री सुनील ओटवानी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल
बोर्ड पर निर्णय
22.10.2021

संजय के. अग्रवाल, जे

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 के साथ पठित, जैसा कि संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि

वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा एम.जे.सी. संख्या 04/2018 में दिनांक 23/09/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध है, साथ ही आई.ए. संख्या 1, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपील दर्ज करने में विलंब के लिए क्षमा याचना के लिए आवेदन, क्योंकि यह अपील 84 दिनों से बाधित है।

2. विलंब के लिए क्षमा याचना के आवेदन में, अपीलार्थी ने यह तर्क दिया है कि उसने इस अपील को दर्ज करने के लिए अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और उसे पूरी फाइल सौंप दी, हालांकि, अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा इसे गलत जगह रख दिया गया और फाइल को पुनर्निर्मित करने के पश्चात, अपील को 84 दिनों की सदभाविक विलंब के साथ दर्ज किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी की मां को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से गुजरना पड़ा और इसलिए, अपील को समय पर दर्ज नहीं किया जा सका, इस प्रकार, अपील दर्ज करने में 84 दिनों की विलंब, जो कि सदभाविक है, को क्षमा किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी /राज्य द्वारा विलंब के लिए क्षमा याचना के आवेदन का जवाब दर्ज किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अपील 84 दिनों की अत्यधिक विलंब के साथ दर्ज की गई है और यह परिसीमा अधिनियम द्वारा बाधित है, इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे विलंब के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

4. श्री विवेक चोपड़ा, अपीलार्थी के अधिवक्ता , ने यह तर्क दिया कि हाल ही में, **महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन विभाग) बनाम बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड**[1] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि हालांकि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, लेकिन अपवाद के रूप में, छोटी विलंब को क्षमा किया जा सकता है। उन्होंने निर्णय के कंडिका 63 का हवाला दिया और यह तर्क दिया कि हालांकि

1 (2021) 6 एससीसी 460

उस मामले में, पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था और विलंब के लिए क्षमा याचना का आवेदन खारिज कर दिया गया था, हालांकि, इस मामले में, अपील दर्ज करने में 84 दिनों की विलंब के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है, इसलिए, विलंब के लिए क्षमा याचना का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के आलोक में अपील दर्ज करने में 84 दिनों की विलंब को क्षमा किया जाना चाहिए।

5. श्री सुनील ओटवानी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, ने यह तर्क दिया कि बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में ही, सर्वोच्च न्यायालय ने 75 दिनों की विलंब को लंबी विलंब माना और इसे क्षमा करने से इनकार कर दिया, इसलिए, इस मामले में 84 दिनों की अत्यधिक विलंब , जो कि पर्याप्त कारण दिखाए बिना है, को क्षमा नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं, उनके विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का बहुत सावधानी से अध्ययन किया है।

7. इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 के साथ पठित, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अपील को 84 दिनों की विलंब के साथ क्षमा किया जा सकता है, जबकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम/वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है?

8. उक्त प्रश्न का विचार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले में किया गया था, जहां उनके लॉर्डशिप ने निम्नलिखित दो प्रश्नों सहित चार प्रश्न तैयार किए थे :–

> "1 से 2 xxx xxx xxx xxx

3. क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दर्ज करने में विलंब को क्षमा किया जा सकता है, और यदि हां, तो किस हद तक?

4. क्या, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दर्ज करने में विलंब को क्षमा करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का अनुप्रयोग वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की योजना द्वारा बहिष्कृत है? ”

9. इसके पश्चात , उनके लॉर्डशिप ने इस मुद्दे पर विचार किया और निर्णय के कंडिका 23 में यह निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 को अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित करने से यह स्पष्ट होता है कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान धारा 37 के तहत दर्ज की गई अपीलों पर लागू होंगे और आगे यह माना कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 उक्त अपीलों पर लागू होगी, जो कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 43 और परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के आधार पर है। रिपोर्ट के कंडिका 23 में यह कहा गया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"23. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37, जब धारा 43 के साथ पठित की जाती है, यह स्पष्ट करती है कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान धारा 37 के तहत दर्ज की गई अपीलों पर लागू होंगे। यह हमें परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 की ओर ले जाता है, जो 90 दिनों और 30 दिनों की परिसीमा अवधि प्रदान करते हैं, यह इस आधार पर कि अपील किसी अन्य न्यायालय से उच्च न्यायालय में है या उच्च न्यायालय के भीतर है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 उक्त अपीलों पर लागू होगी, जो कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 और परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के आधार पर है।”

10. इस प्रकार, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत प्रस्तुत अपील में, अपील दर्ज करने में विलंब को क्षमा किया जा सकता है।

11. अगला प्रश्न जो विचारणीय है, वह यह है कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दर्ज करने में विलंब को क्षमा करने के लिए परिसीमा

अधिनियम की धारा 5 का अनुप्रयोग वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की योजना द्वारा बहिष्कृत है?

12. इस मुद्दे का उत्तर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले में दिया गया है, जहां यह प्राधिकृत रूप से कंडिका 63 में माना गया है:–

> "63. उक्त और मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत त्वरित निपटान के उद्देश्य को देखते हुए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दर्ज की गई अपीलों के लिए, जो परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(1–A) द्वारा शासित हैं, 90 दिनों, 30 दिनों या 60 दिनों से अधिक की विलंब को अपवाद के रूप में और नियम के रूप में नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। एक उपयुक्त मामले में जिसमें एक पक्षकार ने अन्यथा सदभाविक तरीके से कार्य किया है और लापरवाही से नहीं, न्यायालय के विवेक में, ऐसी अवधि से अधिक की छोटी विलंब को क्षमा किया जा सकता है, हमेशा यह ध्यान में रखते हुए कि तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि विपरीत पक्षकार ने इक्विटी और न्याय में वह प्राप्त कर लिया हो सकता है, जो अब पहले पक्षकार की निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही के कारण खो सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, उनके लॉर्डशिप ने यह माना है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दर्ज की गई अपीलों के लिए, जो परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(1–A) द्वारा शासित हैं, 90 दिनों, 30 दिनों या 60 दिनों से अधिक की छोटी विलंब को न्यायालय के विवेक में, अपवाद के रूप में और नियम के रूप में नहीं क्षमा किया जा सकता है।

14. अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के कंडिका 63 के संदर्भ में विलंब को क्षमा करने के लिए मामला बनाया है?

15. अपीलार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब के लिए क्षमा याचना के लिए अपील के साथ दर्ज किए गए आवेदन में, कंडिका 2 और 3 में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं:–

> "2) कि, निचली अदालत द्वारा आदेश पारित होने के पश्चात , अपीलार्थी ने इस अपील को दर्ज करने के लिए अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और उसे पूरी फाइल सौंप दी, हालांकि, अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा इसे गलत जगह रख दिया गया और इसे पुनर्निर्मित करने के पश्चात , यह अपील दर्ज की जा रही है, जिसके लिए अपीलार्थी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता और इस प्रकार हुई विलंब सदभाविक है और जानबूझकर नहीं।
> 3) अपीलार्थी कहता है और प्रस्तुत करता है कि विलंब का एक कारण यह भी था कि अपीलार्थी की मां को विभिन्न बीमारियों से गुजरना पड़ा और उसे अपनी मां का इलाज कराने के लिए नई दिल्ली जाना पड़ा और दिसंबर 2019 का पूरा महीना और उसके पश्चात अपीलार्थी को अपनी मां की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के पश्चात विभिन्न फॉलोअप के लिए जाना पड़ा और इसलिए अपीलार्थी अपनी मां के साथ था और इस प्रकार अपील तैयार करने के लिए अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका और इसलिए भी कुछ विलंब हुई जो सदभाविक है और जानबूझकर नहीं और इसलिए विलंब को क्षमा किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विलंब के लिए क्षमा याचना के आवेदन के कंडिका 2 का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी की ओर से उठाया गया पहला आधार यह है कि फाइल अधिवक्ता को सौंप दी गई थी और इसे गलत जगह रख दिया गया और इसके पुनर्निर्माण में समय लगा, इसलिए, अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। अधिवक्ता को फाइल सौंपने की तारीख के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है और इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई अन्य विवरण प्रदान नहीं किया गया है। इसी तरह, न तो कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई अन्य विवरण दिया गया है जो यह सुझाव दे कि चिकित्सा कारणों के कारण, अपील को समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अपीलार्थी यहां पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहा है कि इस अपील

को दर्ज करने में 84 दिनों की लंबी विलंब को क्षमा किया जाए। तदनुसार, अपील दर्ज करने में विलंब के लिए क्षमा याचना का आवेदन यहां खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप, यह मध्यस्थता अपील भी खारिज की जाती है। कोई व्यय नहीं।

एसडी/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

एसडी/–
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur